

जिला शुल्क समिति: आखिर कहा गई 2018 में जमा स्कूलों की शिकायत वाली फाइलें

उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडलीय शुल्क समिति में जमा हुए थे सभी नामचीन स्कूलों के रिकॉर्ड, आज तक नहीं हुआ किसी स्कूल के रिकॉर्ड का खुलासा

2 टूक संवाददाता

बरेली। शहर के नामचीन स्कूलों पर लगातार लगाने के लिए उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने 2018 में स्वतंत्र स्वचित पोषित मंडलीय शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया था। जिसके तहत प्रदेश के सभी नामचीन स्कूलों से फीस और आय-व्यय का पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड मांगा था। इस साल शहर में सभी स्कूलों ने 5 वर्ष का रिकॉर्ड मांगा था। जिससे की पता चल सके कि स्कूल वालों को कितनी आय हो रही है और कितनी फीस मिल रही है। स्कूल ये रिकॉर्ड डीआईओएस आफिस में जमा है। इन रिकॉर्ड का क्या हुआ ... अब से रिकॉर्ड कहा है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। चर्चा ये भी है



कि पोल खुलने के डर से स्कूल वालों ने शिक्षा विभाग में सेटिंग कर ली है। यही कारण है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग ने एक भी स्कूल पर कोई एक्शन नहीं लिया और एक भी

65 स्कूलों की शिकायत भी हो गई गायब

साल 2018 में मंडलीय शुल्क समिति में अभिभावकों की ओर से 65 स्कूलों की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिससे की स्कूलों पर एक्शन हो सके। दिखावे के लिए समिति की ओर से इन स्कूलों को सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी कर कारण पूछा लेकिन किसी भी स्कूल पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आलम ये रहा कि समय के साथ मामला उठे बस्ते में चला गया। अब ये शिकायतों की फाइल कहा है इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसके बाद जिला समिति का गठन किया गया। लेकिन इस समिति ने भी स्कूलों पर कोई एक्शन नहीं लिया।

समिति ही है अधूरी, तो कैसे बने बात

शुल्क समिति अभी भी अधूरी है। क्योंकि 2018 में समिति के सीए ने स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए जमकर चोटाटा किया। इसी बीच मामले की पोल खुल गई। आलम ये रहा कि डीएम को सीए को कमेटी से बाहर करना पड़ा इसके अलावा भी दो अन्य सदस्यों के पद अभी भी खाली पड़े हैं। जबकि कमेटी पूरी नहीं हो जाता तब तक जिला शुल्क समिति आगे की कार्रवाई नहीं कर सकती। हर बार जिला शुल्क समिति की मीटिंग से पहले इसी बात को लेकर मीटिंग को रोक दिया जाता है।

इस वर्ष भी नहीं बुलाई बैठक

शासन के आदेश है कि जिला समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में शैक्षिक सत्र की शुरु में और बीच सत्र समय समय पर करते रहेंगे। लेकिन कोरोना के नाम पर जिला प्रशासन ने बैठक को बुलाना भी मुनासिफ नहीं समझा। अब ये वर्ष भी धीरे धीरे गुजरने वाला है। लेकिन जिला शुल्क समिति की बैठक बुलाने का समय नहीं मिला। ऐसे में साफ है कि जिला शुल्क समिति स्कूलों को ही फायदा पहुंचाने के लिए बैठक बुलाने में टाल मटौल कर रही है। अफसर अभिभावकों की बात कितनी सुन रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक कमेटी ने मुख्य - मुख्य बिंदु पर आज तक बात ही नहीं की।

सड़क बनने के बाद आए ऊपर करने है मेनहोल



बरेली। बीते कई महीनों से बद्दहाल पड़ी माल गोदाम सड़क अभी कुछ ही सप्ताह पहले नए सीर से बनी है। सड़क बने अभी कुछ ही दिन बीते हैं और विभाग ने जगह जगह इसमें गड्डे कर दिए हैं। लाखों की लागत से तैयार हुई नई सड़क पर जगह जगह 1-1 फीट गहरे गड्डे बने हुए हैं। विभाग ने मेनहोल को ऊंचा करने के लिए गड्डे बना दिए हैं। जबकि इन मेनहोल को ऊंचा करने के लिए ये प्रक्रिया सड़क बनने के पहले ही होनी थी। जिससे की सड़क को समतल बनाया जा सके। लेकिन नगर निगम ने जगह जगह गड्डे कर सड़क को पहले से भी अधिक बद्दहाल कर दिया है। आलम ये है कि इन सड़क से लोगों का गुजरना भी मुश्किल है। चौपला तिराहे से लेकर सुभाषनगर मोड़ तक बुल्डोजर से जगह जगह गड्डे कर दिए गए हैं। जबकि अभी तक इन गड्डों को नहीं भरा जा सका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यदि इन गड्डों के कारण कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। से हाल लगभग लगभग पूरे शहर का ऐसा ही है। क्योंकि सिबर लाइन बिछाने के बाद सड़क का निर्माण कार्य करा दिया है। अब बरसात का पानी जगह जगह से जमा होने से सड़क धसने लगी है। 2 टूक

42 स्कूलों में फंसा बिजली कनेक्शन

डीएम की फटकार के बाद भी विभाग ने नहीं दिया स्कूलों को बिजली कनेक्शन

2 टूक संवाददाता

बरेली। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बिजली कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है कायाकल्प योजना के तहत तमाम स्कूलों में सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजना की शुरुआत हुई थी बावजूद इसके अभी भी कई स्कूल अंधेरे में हैं। शहर और देहात क्षेत्र के मिलाकर अभी भी 42 स्कूल ऐसे हैं। जिनको अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है। जबकि बीते दिनों पहले ही जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अफसरों को फटकार भी लगाई थी। लेकिन अभी तक बिजली विभाग की ओर से बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। बिजली कनेक्शन के लिए बीते कई दिनों से स्कूल के शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं मगर विभागीय अफसर भी दूसरी विभाग पर जिम्मेदारी होने की बातें कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं।

खोखले हैं 1800 स्कूल के दावे

बेसिक शिक्षा अधिकारी हर बार कायाकल्प योजना के तहत जिले के 1800 स्कूलों को कायाकल्प करने का हवाला देते हैं जबकि हकीकत कुछ और ही है अभी तक क्षेत्र के 42 स्कूल ऐसे हैं जिसमें बीते कई महीनों से बिजली कनेक्शन के लिए मांग हो रही है तब भी बेसिक शिक्षा विभाग इन स्कूलों में बिजली कनेक्शन तक नहीं करा पा रहा है ऐसे में साफ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर किस तरह से कार्य कर रहे हैं। सिर्फ कागजों में ही अपनी पीठ थपथपा ने के लिए कायाकल्प योजना का गुणगान कर रहे हैं।

किराए के भवनों को भी नहीं दे रहे

जो स्कूल खुद के भवन में संचालित हो रहे हैं इनमें तो बिजली कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है बावजूद इसके शहर और देहात क्षेत्र में कई प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो कि किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं ऐसे स्कूलों में बिजली कनेक्शन के नाम पर विभाग नियमों का हवाला दे रहे हैं एक तरफ शिक्षा विभाग का नियम है कि स्कूल के भवन स्वामी की ही जिम्मेदारी ही होती है। वहीं दूसरी ओर भवन स्वामी स्कूल कनेक्शन के लिए शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस खींचतान में बीते कई वर्षों से अनेकों स्कूल में भी तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुंच पाया।

बरेली कॉलेज: प्राचार्य आफिस के कैमरे बंद या खराब

जिन दिन हुई थी कर्मचारी और छात्र नेता में हाथापाई उस दिन भी बंद मिले थे कैमरे

2 पूर्व प्राचार्य से भी हो चुकी अश्रुता, प्राचार्य कुर्सी का हुआ था अपमान, फिर भी बंद थे सीसीटीवी

2 टूक संवाददाता

बरेली। लाखों करोड़ों का बजट फिर भी बरेली कॉलेज में सुरक्षा हमेशा से बेपटरी ही रहती है। कहने तो कॉलेज में हर साल सीसीटीवी पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन ये किसी काम के नहीं रहे। कम एबीवीपी के हंगामे के बाद पुलिस ने जब आरोपी छात्रों की पहचान केलिए प्राचार्य आफिस के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पुलिस के कुछ हाथ नहीं आया। क्योंकि बरेली कॉलेज के प्राचार्य आफिस समेत पूरे कार्यालय के सीसीटीवी

तो पता चल जाती किसकी है गलती

ये पूरा मामला कुछ दिन पूर्व फार्म जमा करने को लेकर कॉलेज के एक कर्मचारी और छात्र नेता की बहस से शुरू हुआ। छात्र नेता का कहना है कि पहले कर्मचारी ने हाथापाई की और कर्मचारी का कहना है कि पहले छात्र नेता ने हाथापाई की। सच क्या है इस पर सवाल बरकरार है। यदि कार्यालय के सीसीटीवी सही होते जो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। सीसीटीवी की मदद से सच का पता चल जाता कि गलती किसकी है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन ने एबीवीपी के खिलाफ लूट की शिकायत भी थाना बारादरी में दर्ज करा दी है। क्योंकि कॉलेज की ओर से छात्र नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि हंगामा के नाम पर छात्र नेताओं ने कैश काउंटर से रुपए लूट लिए।

खराब मिले। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किसी भी बड़ी घटना के समय आखिर बरेली कॉलेज के प्राचार्य आफिस और कार्यालय के सीसीटीवी एन मौके पर खराब हो जाते हैं या जानबूझ कर बंद किए जाते हैं। जिस कारण आज तक किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। ऐसा इस बार भी हुआ सोमवार को हुए हंगामा के दौरान

केस 1
साल 2018 में एलएलबी की मुख्य परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र चोरी हुए थे। उस समय प्रश्न पत्र प्राचार्य आफिस के पास लॉकर में रखे जाते थे। लेकिन सीसीटीवी न होने से मामले का आज तक खुलासा नहीं हो सका।

केस 2
इसी साल सखस के आंदोलन के दौरान बरेली कॉलेज में ताला तक लगाया पड़ा था। उस समय भी सीसीटीवी कैमरों की कमी बरेली कॉलेज प्रशासन को लगी थी।

केस 3
2019 में अपनी मांग को लेकर एक अस्थायी कर्मचारी ने प्राचार्य आफिस में जहर खा लिया था। जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती भी कराया। पुलिस ने हकीकत जानने केलिए सीसीटीवी खंगाले लेकिन इस साल भी सीसीटीवी बंद ही मिले थे।

डॉ. अजय शर्मा के साथ भी हो चुकी घटना

बता दें कि बरेली कॉलेज में साल 2018 में पूर्व प्राचार्य डॉ. अजय कुमार शर्मा के साथ भी बदसलूकी हो चुकी है। कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान कुछ ने प्राचार्य की कुर्सी पर थूककर, जूते रखकर कुर्सी का अपमान तक किया था आलम ये था कि प्राचार्य के साथ धक्का मुक्की भी हुई। तब भी आफिस के कैमरे बंद थे। जिस कारण आरोपी कर्मचारियों की पहचान नहीं हो सकी। मजबूरन प्राचार्य ने कई दिनों के लिए बरेली कॉलेज बंद कर दिया था।

बरेली कॉलेज में कई अहम सीसीटीवी के बंद या खराब होने से कई अहम सबूत हाथ नहीं लगे।



Heartiest
Congratulations
To The Entire Staff Of
Ab Baat Hogi
2 Took
Bareilly
On The Foundation Day



Haji Shakeel Qureshi
Chairman & Managing Director
Marya Frozen Agro Foods P. Ltd.
Chairman
Marya Day Agro Foods P.Ltd.